Power Shortage in States

+

*65. **Shri Indrajit Gupta:**
Shri Linga Reddy:
Dr. L. M. Singhvi:
Shri Warior:
Shri Prabhat Kar:
Shri Vasudevan Nair:

Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state:

(a) whether the problem of Power shortage has been solved in the States where there was power shortage on account of the failure of recent rains;

(b) if so, to what extent; and

(c) if not, how the Government propose to solve the problem in the South and North Indian regions?

The Minister of State in the Ministry of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao): (a) to (c). The hon. Minister will lay a statement on the Table of the Lok Sabha on the 24th February, 1966, which would *inter-alia* cover the information asked for in this question.

Shri S. M. Banerjee: Sir, I rise to a point of order. (*Interruption*).

Shri M. L. Dwivedi: This was given a month before, and he says that a statement will be laid on the Table. The reply should come now.

Shri S. M. Banerjee: This question was given notice of in the month of January, and now we find on the 17th February, when a month has elapsed, that the answer will be given at some future date. that the hon. Minister of Irrigation and Power will make a statement on the 24th February. This is most unfortunate. I do not know why they are treating these things in this way. You have admitted the question, and it should be answered in time. They can say that they are collecting the data or the information is not available. Can they say that this will be answered on the 24th February? I do not know why we have been treated with such contempt.

Mr. Speaker: I see at least some substance in this. If a question is put to a Minister and if the answer is not ready with him, he should inform my office at least that we should strike it off or postpone it to some other day. If the data is not available or has not yet been collected, the Minister should say. "We are making efforts. It has not yet been collected. It would take some time and we will answer after that". Some definite information must be given, so that the question that has been put on the list is answered.

Dr. K. L. Rao: We accept what you have directed. The point is, we have got some information, but it is not complete. There are seven States where there is shortage of power. We have requested the seven States to send the information. Some of them have not sent. We are awaiting the information. If any interim information is required, we will give that.

Shri S. M. Banerjee: Kindly give that.

Mr. Speaker: I will put this question on some other day so that it might be answered.

World Population Problem

+

*66. **Shri Rameshwar Tantia:**
Shri Narayan Reddy:
Shri Himatsingka:
Shri Onkar Lal Berwa:
Shri Lahtan Chaudhry:
Shri Bhagwat Jha Azad:
Shri M. L. Dwivedi:
Shri S. C. Samanta:
Shri Subodh Hansda:
Shrimati Savitri Nigam:
Shri P. C. Borooah:

Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that India has proposed to the U. N. to take new measures to tackle the world population problem;

(b) if so, whether any resolution in this regard has been put forward by India in the U.N.; and

(c) whether any decision has been taken in this regard in the U.N.?

The Minister of Health and Family Planning (Dr. Sushila Nayar): (a) to (c). Yes, Sir. The Indian delegate at the U.N., on behalf of the Co-sponsers, introduced in the General Assembly, a resolution on the new measures to be taken to tackle the world population problem; but the consideration of this item was post-poned to the twenty-first session of the Assembly.

श्री रामेश्वर टांटिया: क्या हम ने अपने देश में पापुलेशन प्राबलैम को हल कर लिया है ? अगर नहीं किया तो कहां तक उसके लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं ? आज भी ढाई प्रतिशत के हिसाब से हर साल हमारी जनसंख्या बढ़ रही है । हम ने इसको रोकने के लिए क्या मैथर अपनाये हैं, क्या उपाय किये हैं और किस तरह से हम समझते हैं कि हमारी पापुलेशन स्टेबल रहे, वह न बढ़े ?

डा० सुशीला नायर : हिन्दुस्तान में पापुलेशन ढाई प्रतिशत के हिसाब से तो नहीं लेकिन पिछली सैंसस से यह पता चला है कि 2.1 प्रतिशत के हिसाब से बढ़ी है । लेकिन यह प्राबलैम खाली हिन्दुस्तान का ही नहीं है, सारी दुनिया का यह प्राबलैम है । सारी दुनिया की पापुलेशन तीन प्रतिशत के हिसाब से बढ़ रही है । इसलिए कोई आठ दस देशों ने मिल कर यह प्रस्ताव यू० एन० के सामने रखा था कि इसके बारे में कुछ ठोस कदम उठाने चाहियें और इस बारे में विचार विनिमय होना चाहिये ।

श्री रामेश्वर टांटिया: अभी मंत्री महोदय ने कहा है कि 2.1 प्रतिशत के हिसाब से बढ़ रही है । वह भी बहुत ज्यादा रेट है । शायद कुछ देशों में एक या डेढ़ परसेंट के हिसाब से ही पापुलेशन बढ़ रही है और वह भी उन देशों में जिनकी पापुलेशन हम से कहीं कम है । सरकार इतने जो प्रयत्न कर रही है पापुलेशन ग्रोथ को रोकने के बारे में, क्या उन से सरकार को संतोष है और अगर नहीं है तो क्या कोई ऐसे मैथर लायेगी सरकार जिससे यह बढ़ती हुई पापुलेशन रुके ?

डा० सुशीला नायर: सरकार को सर्वथा संतोष है कि हम जो काम कर रहे हैं बहुत तेजी से वह आगे बढ़ रहा है और उसके परिणाम भी यथासमय देखने में आयेंगे । एक दिन में परिणाम नहीं मिल सकते हैं । कार्यक्रम क्या है, प्रोग्राम क्या हैं वह तो क्वेश्चन आवर में बताना कठिन है । यह सब इतिला रिपोर्ट्स में तथा दूसरी जगह मौजूद है और माननीय सदस्य देख सकते हैं ।

श्री अ० प्र० शर्मा : आप ने कहा है कि काम तेजी से बढ़ रहा है । पापुलेशन घटाने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है या बढ़ाने की दिशा में ?

श्री ओंकार लाल बेरवा : बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकने के लिए विदेशों से उपकरण मंगाये जाते हैं और उनका यहां पर प्रयोग किया जाता है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि परिवार नियोजन सप्ताह मनाने के बारे में जो एक आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी है, जो एक सर्वे किया है, उसके अन्दर उसने यह कहा है कि जो लूप है वह नाकामयाब रहा है और 78 प्रतिशत केसिस में नाकामयाब सिद्ध हुआ है । यदि हां तो सरकार ने इसके बारे में क्या उपाय किये हैं ?

डा० सुशीला नायर : ऐसी कोई बात नहीं है । लूप करीब चार लाख इस देश में डाले गये हैं और उसका जो फेल्योर रेट है वह किसी जगह पर 3 प्रतिशत रहा है किसी जगह इससे कुछ ज्यादा लेकिन किसी जगह पर भी दस प्रतिशत से अधिक नहीं रहा है ।

श्री ओंकार लाल बेरवा : फेल्योर जो यह हुआ है इसकी रिपोर्ट आपको क्या मिली है ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने जवाब दे दिया है ।

श्री भगवत झा आजाद : राष्ट्र संघको जन संख्या की समस्या को हल करने के बारे में नए उपायों का सुझाव देने के पूर्व क्या सरकार ने जो अभी उपाय प्रचलित हैं उन उपायों को वहां तक पहुंचाया है जहां तक इन को पहुंचाने की आवश्यकता थी और यदि उन्होंने ऐसा नहीं किया है और सफलता नहीं मिली है तो इस तरह के सुझाव देने का क्या कारण है ?

डा० सुशीला नायर : जो कहा गया है वह सिर्फ यह कहा गया है कि यू० एन० अपनी स्पेशेलाईज्ड एजेंसीज के जितने कार्य हैं उनको एक दूसरे के साथ जोड़ कर कोआर्डिनेट करके अपनी डेमोग्राफिक एक्टिविटीज को बढ़ाये। इसमें यह भी कहा गया है कि पापुलेशन कमिशन के सामने क्या प्रायोरिटीज होनी चाहिऐ। यह प्रापोजल रखी है । इस का यह अर्थ नहीं है कि जो कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं उनको छोड़ कर कोई नया कार्यक्रम बनाने की बात है । लेकिन इस पर विचार कर के सारी दुनिया में जिन जिन देशों में तेजी से आबादी बढ़ रही है वहां किस क्रम से, किन प्रायोरिटीज से यह कार्य होना चाहिये, यू० एन० इस बारे में कुछ गाईडेंस दें देशों को । इतना ही उस प्रस्ताव में कहा गया है ।

श्री म० ल० द्विवेदी : विश्व की जनसंख्या को कम करने की दिशा में भारत जब योगदान दे रहा है तो क्या मैं जान सकता हूं कि भारत की समस्त जनता पर यह परिवार नियोजन का नियम एक सा लागू होता है या किसी विशेष वर्ग पर ही लागू होता है ? यदि सभी वर्गों पर एक सा लागू नहीं होता है तो क्या इस सम्बन्ध में कोई कानून बनाये जाने की सम्भावना है ?

डा० सुशीला नायर: कोई कानून बनाने का तो सवाल नहीं है । यह बात सही है कि परिवार नियोजन का काम दुनिया में सभी देशों से ज्यादा विस्तार से और ज्यादा तीव्रता से हमारे देश में किया जा रहा है । इस लिए जो देश भी हम से सलाह मश्विरा मांगते हैं उनको हम मदद देते हैं। लेकिन देश के अन्दर कहीं पर काम ज्यादा अच्छा हुआ है और कहीं पर ज्यादा अच्छा नहीं भी हुआ है । सारे देश में एक समान काम नहीं हुआ है ।

Shri S. C. Samanta: The hon. Minister said that India with some other countries brought a resolution. May I know whether this population problem is the same in all the countries which have joined us?

Dr. Sushila Nayar: No. Sir; the population problem is not the same in all the countries. May I say that the countries that brought this resolution were Denmark, Ghana, India, Iraq, Guinea, Libya, Nepal, Norway, Nigeria, Pakistan, Sweden, Syria, UAR and Yugoslavia. Some of these countries like Sweden, Norway etc. have a very low birth rate as compared to some of the others.

Shri Subodh Hansda: Sir, various methods have been tried in our country. May I know whether the Government have any idea as to which of the methods have been successful and whether in that resolution any concrete suggestion has been given as to which method should be adopted for population control?

An hon. Member: Do not marry.

Dr. Sushila Nayar: Sir, I could not clearly follow the question.

Mr. Speaker: Nor could I. Would he repeat it?

Some hon. Members *rose*—

Mr. Speaker: Shrimati Savitri Nigam—probably he is not serious himself.

Shrimati Savitri Nigam: In view of the fact that much pioneering work has been done by India in this field, which are the countries which have sent their workers to India

for training and how far have we been able to satisfy them?

Dr. Sushila Nayar: We have been training workers from 10 to 15 countries every year. I am afraid, I do not have the list of those countries with me just at present. But I will mention a few. Some of them are our neighbouring countries like Nepal, Afghanistan and Pakistan. May I say that some technical assistance in family planning has been asked from us even by highly developed countries such as the United States?

Mr. Speaker: The Question Hour is over.

Shri Shivaji Rao S. Deshmukh: May I suggest that Question No. 78, which is a very important question, may be taken up now before you take up any other item? It relates to Krishna-Godavari waters dispute.

Mr. Speaker: I cannot take it up now. The Question Hour is over.

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

कृषि ऋण निगम

*67. श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री यशपाल सिंह :
श्री बाल्मीकी :
श्री बागड़ी :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री भानु प्रकाश सिंह :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री ब० ब० राजू :
श्री हेम राज :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यों में कृषि ऋण निगम स्थापित करने के सम्बन्ध में रक्षित बैंक द्वारा किये गये अध्ययन के क्या परिणाम निकले हैं ;

(ख) उक्त निगम के कब तक स्थापित हो जाने की सम्भावना है ; और

(ग) इस निगम के मुख्य कार्य क्या होंगे और इसके कार्य संचालन के लिए कितना धन दिया जायेगा तथा किस स्रोत से ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) से (ग). संस्थाओं द्वारा कृषि सम्बन्धी ऋणों के लिये किये जा रहे वर्तमान प्रबन्धों की जांच करने के लिए, कुछ समय पहले रिजर्व बैंक के गवर्नर की अध्यक्षता में जो अनौपचारिक दल नियुक्त किया गया था उसने सिफारिश की थी कि पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, उड़ीसा, राजस्थान राज्यों और मणिपुर तथा त्रिपुरा के संघीय राज्य क्षेत्रों में कृषि ऋण निगम स्थापित किये जायें ताकि इन क्षेत्रों में सहकारी बैंकों द्वारा जो ऋण सुविधाए दी जा रही हैं वे बढ़ायी जा सकें । अनौपचारिक दल के अनुसार, निगमों की शेयर पूंजी में मुख्यतः सम्बद्ध राज्य सरकारें तथा रिजर्व बैंक रुपया लगायेगा पर ये निगम रिजर्व बैंक से ऋण ले सकेंगे । अनौपचारिक दल की सिफारिशें अभी विचाराधीन हैं ।

Aid from abroad during Third Plan

*68. **Shri Bhagwat Jha Azad:**
Shri M. L. Dwivedi:
Shri S. C. Samanta:
Shri Subodh Hansda:
Shri P. C. Borooah:
Shri Linga Reddy:
Shrimati Savitri Nigam: